Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAJASTHAN

JUNIOR ACCOUNTANT

प्रथम प्रश्न पत्र

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

भाग – 1

राजस्थान का सामान्य ज्ञान

SIERRA INNOVATIONS

RAJASTHAN JR. ACCOUNTANT

CONTENTS

राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति		
1.	प्राचीन राजस्थान का इतिहास	1
	• परिचय	1
	• प्राचीन सभ्यताएँ	4
	• महाजनपद काल	8
	• मौर्यकाल	9
	• मौर्योत्तर काल	9
	• गुप्तकाल	9
	• गुप्तोत्तर काल	9
2.	मध्यकाल राजस्थान का इतिहास	11
	• प्रमुख राजवंश एवं उनकी विशेषताएँ	
	• राजस्थान की रियासतें और अंग्रेजों के साथ संधियाँ	
3.	आधुनिक राजस्थान का इतिहास	50
	• 1857 की क्रांति	50
	• प्रमुख किसान आन्दोलन	53
	• प्रमुख जनजातीय आन्दोलन	56
	• प्रमुख प्रजामण्डल आन्दोलन	58
	• राजस्थान का एकीकरण	62
4.	राजस्थान कला एवं संस्कृति	66
	• राजस्थान के त्यौहार	66
	• राजस्थान के लोक देवता	73
	• राजस्थान की लोक देवियाँ	78
	• राजस्थान के लोक सन्त एवं सम्प्रदाय	81
	• राजस्थान के लोकगीत	87

	• राजस्थान की लोकगायन की शैलियाँ	89
	• राजस्थान के संगीत	89
	• राजस्थान के लोक नृत्य	91
	• राजस्थान के लोकनाट्य	95
	• राजस्थान की जनजातियाँ	98
	• राजस्थान की चित्रकला	101
	• राजस्थान की हस्तकलाएँ	106
	• राजस्थान का साहित्य	109
	• राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ	114
	• राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र	115
5.	राजस्थान की स्थापत्य कला	121
	• किले एवं स्मारक	121
	• राजस्थान के धार्मिक स्थल	130
	• राजस्थान की सामाजिक प्रथाएँ एवं रीति–रिवाज	134
	• राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व	136
	• वेश–भूषा व आभूषण	141
	राजस्थान का भूगोल	
1.	राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार एवं क्षेत्रफल	145
2.	राजस्थान का भौतिक प्रदेश एवं विभाग	151
3.	राजस्थान का अपवाह तंत्र	163
4.	राजस्थान की झीलें	171
5.	राजस्थान की जलवायु	175
6.	राजस्थान में मृदा संसाधन	182
7.	राजस्थान में वन–संसाधन एवं वनस्पति	187
8.	राजस्थान में खनिज सम्पदा	192
9.	राजस्थान में ऊर्जा स्त्रोत	201
10.	राजस्थान में पशुधन	209
11.	राजस्थान में कृषि एवं सिंचाई परियोजनाएँ	214

12.	राजस्थान की जनसंख्या	223
13.	राजस्थान में वन्यजीव एवं इनका संरक्षण	225
14.	राजस्थान में उद्योग	229
15.	राजस्थान में सूखा, अकाल व मरुस्थलीकरण	233
	राजस्थान : राजव्यवस्था	
1.	राज्य की कार्यपालिका	234
2.	राज्य का राजनीतिक घटनाक्रम	242
3.	सचिवालय	248
4.	संभाग	252
5.	जिला	253
6.	उपखण्ड अधिकारी	255
7.	तहसीलदार	256
8.	पुलिस प्रशासन	257
9.	पटवारी	260
10.	राज्य निर्वाचन आयोग	261
11.	राजस्थान लोक सेवा आयोग **(RPSC)**	263
12.	राज्य सूचना आयोग	264
13.	स्थानीय स्वशासन	266
14.	नगरीय संस्थाएं	271
15.	नगरीय संस्थाएं बोर्ड	275
16.	राज्य वित्त आयोग	277
17.	लोकायुक्त	278
18.	राज्य मानवाधिकार आयोग	279
19.	राज्य महिला आयोग	281
20.	उच्च न्यायालय	281
21.	लोकनीति	285
22.	विधिक अधिकार	287

राजस्थान : अर्थव्यवस्था

1.	अर्थव्यवस्था	290
2.	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	291
3.	निर्धनता / गरीबी (Poverty)	297
4.	राजस्थान आर्थिक–समीक्षा 2020–21	303
5.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	305
6.	औद्योगिक विकास	307
7.	आधारभूत संरचना का विकास	310
8.	पशुधन (Live Stock)	313
9.	वन रिपोर्ट	315

राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति

राजस्थान का एकीकरण

- 18 जुलाई 1947 को "भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम" पारित हुआ "धारा-8" के तहत अंग्रेजो की देशी रियासतों के साथ संधिया समाप्त कर दी गई ।
- (यह प्लान 3 जून को आ गया था लेकिन 18 जुलाई को संसद में पास हुआ)
- "5 जुलाई 1947" को "रियासती विभाग" की स्थापना की गई । जिसके "अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल" व "सचिव वी.पी. मेनन" थे ।
- इस विभाग ने घोषणा कि "10 लाख से अधिक" जनसंख्या तथा "1 करोड आय" वाली रियासतें आजाद रह सकती हैं ।
- इस समय राजस्थान में ऐसी केवल 4 रियासतें थी ।
  1. मेवाड
  2. मारवाड
  3. जयपुर
  4. बीकानेर
- आजादी के समय राजस्थान में "19 रियासते 3 ठिकाने व 1 केन्द्र शासित प्रदेश" था ।

  3 ठिकाने
  1. लावा (टोंक से अलग)
  2. नीमराणा (अलवर से अलग)
  3. कुशलगढ (बांसवाडा से अलग किया)

  1 केन्द्र शासित प्रदेश – अजमेर – मेरवाडा
- इन सभी को मिलाकर 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था ।
- राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले प्रयास "गवर्नर जनरल लिननिथगों" ने किया था ।
- मेवाड महाराणा "भूपाल सिंह" ने राजस्थान, मालवा व सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर "राजस्थान यूनियन" बनाने का प्रयास किया तथा इसके लिए 25 जून – 26 जून 1946 को "उदयपुर" में सम्मेलन किया ।
- बीकानेर महाराजा सार्दुल सिंह (गंगासिंह का बेटा) ने सबसे पहले 7 अगस्त 1947 संविधान सभा में शामिल होने की घोषणा की थी ।

प्रथम चरण :18 मार्च 1948

मत्स्य संघ : नामकरण "के. एम. मुँशी'
पी.एम. :- "शोभाराम कुमावत"

धौलपुर	करौली	अलवर	भरतपुर	नीमराणा ठिकाना
↓	↓	↓	↓	
उदयभानसिंह (राजप्रमुख)	गणेशपाल (उप राजप्रमुख)	राजधानी	उद्घाटन (18 मार्च 1948)	

राजप्रमुख : उदयभानसिंह

- प्रधानमंत्री : शोभाराम कुमावत (अलवर)
- उपप्रधानमंत्री – जुगल किशोर चतुर्वेदी
- मुख्य अतिथि – एन वी गाडगील
- "अलवर" व "भरतपुर" रियासत का नियंत्रण भारत सरकार ने अपने पास पहले ही ले लिया था ।

(क्योंकि अलवर का राजा गांधीजी की हत्या में दिल्ली में नजरबंद था तथा भरतपुर का राजा छोटा था अत: में)

दूसरा चरण: राजस्थान संघ/पूर्व राजस्थान

पी.एम. : गोकुल लाल असावा (25 मार्च 1948)
(9 रियासत और 1 ठिकाना)

1. कोटा – भीमसिंह – राजप्रमुख राजधानी + उद्घाटन 25 मार्च 1948
   एन.वी. गाडविल
2. बून्दी – बहादुर सिंह – वरिष्ट उपराज प्रमुख
3. झालावाड
4. डूंगरपुर – लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराजप्रमुख
5. बाँसवाडा
6. प्रतापगढ
7. कुशलगढ (ठिकाना)
8. टोंक
9. किशनगढ
10. शाहपुरा

- "टोंक" राजस्थान की "एकमात्र मुस्लिम रियासत" थी ।
- "किशनगढ" व "शाहपुरा" रियासतों को तोपो की सलामी नहीं दी जाती थी (छोटी होने के कारण)
- शाहपुरा व किशनगढ रियासतों ने अजमेर मेरवाडा से मिलने से मना कर दिया ।
- "बांसवाडा" के महारावल "चन्द्रवीर सिंह" ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुये कहा था कि-
  "मैं अपने डैथ वारन्ट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ ।"

तीसरा चरण : संयुक्त राजस्थान (राजस्थान संघ + मेवाड)

- पी.एम : माणिक्य लाल वर्मा 18 अप्रैल, 1948 (उदयपुर)
- राजप्रमुख : "भूपालसिंह (मेवाड)"
- वरिष्ठ उपराजप्रमुख : भीमसिंह (कोटा)
- कनिष्ठ उपराजप्रमुख : बहादुर सिंह (बून्दी)
  लक्ष्मणसिंह (डूँगरपुर)
- राजधानी : उदयपुर
- उद्घाटन : उदयपुर (जवाहर लाल नेहरू) 18 अप्रैल 1948
- प्रधानमंत्री : माणिक्य लाल वर्मा

- उपप्रधानमंत्री : गोकुल लाल असावा
- विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा तथा कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे ।
- ''भूपाल सिंह'' को 20 लाख प्रीवी पर्स दिया गया
- औपचारिक प्रीवी पर्स 10 लाख :- राजप्रमुख के वेतन के धार्मिक अनुदान के रूप में 5 लाख रूप में 5 लाख प्रीवी पर्स: राजाओं को दी जाने वाली पेंशन (विलय के बाद)

चौथा चरण : वृहत् राजस्थान
(30 मार्च, 1949)

प्रधानमंत्री :-हीरालाल शास्त्री (जयपुर)

राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आन्दोलन समिति का गठन किया । तथा मांग की शेष बची रियासतों का जल्द से जल्द राजस्थान में विलय किया जायें ।

- संयुक्त राजस्थान + जयपुर + जोधपुर + बीकानेर + जैसलमेर = वृहत् राजस्थान
- ''30 मार्च 1949'' में ''वल्लभ भाई पटेल'' ने जयपुर में उद्घाटन किया ।
- इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है ।

महाराजप्रमुख:	–	''भूपाल सिंह'' (मेवाड)
राजप्रमुख:	–	सवाई मानसिंह द्वितीय (जयपुर)
वरिष्ठ उपराजप्रमुख:	–	हनवन्त सिंह (जोधपुर) भीमसिंह (कोटा)
कनिष्ठ उपराजप्रमुख	–	बहादुर सिंह (बूंदी) लक्ष्मणसिंह (डूँगरपुर)

प्रीवी पर्स:
जयपुर – 18 लाख
जोधपुर – 17.50 लाख

- राजधानी के लिए जयपुर व जोधपुर 2 विकल्प थे अतः इसके समाधान के लिए वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति बनाई तथा इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की ।

समिति के सदस्य:
- वी.आर.पटेल
- एच.सी.पूरी (लेट कर्नल)
- एच.पी. सिन्ह
- हाइकोर्ट : जोधपुर
- शिक्षा विभाग : बीकानेर
- खनिज विभाग : उदयपुर
- वन और सहकारी विभाग : कोटा
- कृषि विभाग : भरतपुर
- ''लावा'' ठिकाने को ''19 जुलाई 1948'' को जयपुर में शामिल किया गया था ।

पाँचवा चरण : संयुक्त वृहत् राजस्थान

''शंकर राव देव समिति'' की सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1949 को ''मत्स्य संघ'' का वृहत् राजस्थान में विलय कर दिया गया ।
प्रधानमंत्री – हीरालाल शास्त्री
राजप्रमुख – सवाई मानसिंह (जयपुर)

समिति के अन्य सदस्य
- आर.के सिद्धवा,
- प्रभुदयाल
- शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रीमण्डल में शामिल कर लिया गया ।

छठा चरण (राजस्थान संघ)

- आबू व देलवाडा सहित 89 गाँव गुजरात में मिलाये गए तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया इसमें गोकुल भाई भट्ट का गाँव हाथल भी शामिल था ।
- यह विलय – 26 जनवरी 1950 को किया गया तथा हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया ।
- इस अनुचित विलय पर पटेल का जवाब था ''राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था वो हमने दे दिया ।''
- हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनित मुख्यमंत्री बनाया गया ।

मनोनित मुख्यमंत्री – हीरालाल शास्त्री जयनारायण व्यास सी.एस. वेंकटाचारी (आई.सी.एस)

निर्वाचित मुख्यमंत्री
1. टीकाराम पालीवाल प्रथम – बाद में उपमुख्यमंत्री बनें ।
2. जयनारायण व्यास
3. मोहन लाल सुखाडिया – राजस्थान के सबसे युवा सी.एम, राजस्थान के सर्वाधिक समय रहने वाले सी. एम.
4. सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री – हीरालाल देवपुरा (16 दिन बाद में मंत्री बनाया गया)
5. पहले चुनाव (1951-52) में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें रामराज्य परिषद को मिली थी ।

4. सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री – हीरालाल देवपुरा (16 दिन बाद में मंत्री बनाया गया)
5. पहले चुनाव (1951–52) में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें रामराज्य परिषद को मिली थी ।

सातवाँ चरण : (वर्तमान राजस्थान)

(1 नवम्बर, 1956)

फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया ।
इसमें 3 सदस्य थें ।

- फजल अली
- हृदय नाथ कुंजः
- के.एम. पणिक्कर (बीकानेर से संविधान सभा में भेजे गये थे ।)

इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर

1. आबू, देलवाडा का राजस्थान में विलय किया गया ।
2. अजमेर – मेरवाडा का राजस्थान में विलय किया गया ।
3. एम.पी. का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया ।
4. राजस्थान का सिरोज एम.पी को दिया गया था ।

नोटः

- 1 नवम्बर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ ।
- उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाडिया थें ।
- ''अजमेर'' को राजस्थान का 26 वाँ जिला बनाया गया ।
- ''अजमेर – मेरवाडा'' एक केन्द्र शासित प्रदेश था जिसमें 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी । यहाँ के मुख्यमंत्री ''हरिभाउ उपाध्याय'' थे ।

नोटः

''हरिभाऊ उपाध्याय'' ने अजमेर का राजस्थान में विलय का विरोध किया था ।

- अजमेर को राजधानी बनाने के लिए विवाद हुआ अतः भारत सरकार ने 3 सदस्यों की एक समिति बनाई । जिसने जयपुर को ही राजधानी बनाने की सिफारिश दी । तथा अजमेर को राजस्व विभाग दिया ।

3 सदस्य समितिः

1. पी. सत्यनारायण राव
2. वी. विश्वनाथन
3. वी. के गुप्ता

नोटः

''आबू देलवाडा'' को राजस्थान में शामिल करने के लिए ''मुनि जिन विजय सूरि'' के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया था । इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इसके सदस्य थे ।

- 7 वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया ।
- अतः राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरूमुख निहाल सिंह थे ।
- 26 वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के पीवी पर्स बन्द कर दिये थें ।
- 1 नवम्बर 2000 को एम.पी. से छत्तीसगढ अलग हो जाने के कारण राजस्थान भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना ।

मनोनीत मुख्यमंत्री

- प्रथम हीरालाल शास्त्री
- द्वितीय सी.एस. वेंकटाचारी (पहला आई.ए.एस मुख्यमंत्री)
- तृतीय जयनारायण व्यास

निर्वाचित मुख्यमंत्री

- प्रथम टीकाराम पालीवाल
- द्वितीय जयनारायण व्यास
- तृतीय मोहनलाल सुखाडिया (1954–71)

सबसे लम्बा कार्यकाल 17 साल सबसे युवा मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा (सबसे कम कार्यकाल 16 दिन) 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में मिला दिया गया ।

राजस्थान के लोक नाट्य

ख्याल

- ऐतिहासिक एवं पौराणिक कहानियों पर संगीत के माध्यम से अभिनय किया जाता है ।
- ख्याल के सूत्रधार को ''हलकारा'' कहा जाता है ।
- मनरंग को ख्याल गायिकी का प्रवर्तक माना जाता है ।

1. कुचामनी ख्याल

- केवल पुरूष भाग लेते है ।
- संस्थापक : ''लच्छीराम'' (10 ख्यालों की रचना)

प्रवर्तक

- मुख्य कलाकार : उगमराज
- मुख्य कहानियाँ – मीरा मंगल
  राव रिडमल
  चाँद नील गिरी

2. जयपुरी ख्याल

- इस ख्याल में महिलाऐ भी भाग लेती है ।
- इसमें नये प्रयोग करने की सम्भावना होती है ।
- कलाकार – हमीदुल्ला (ख्याल भारमली)

3. अलीबख्शी ख्याल

- ये ख्याल ''मुंडावर (अलवर)'' के नवाब अली बख्श के समय शुरू हुई थी ।
- अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है ।
- कृष्ण लीला, निहालदे, चन्द्रावत, गुलकावती आदि ।

4. शेखावाटी ख्याल/चिडावी ख्याल

प्रवर्तक : नानूराम जी
मुख्य कलाकार : ''दुलिया राणा'' (चिडावा)
ख्याल – हीर-रांझा, जयदेव, भृर्तहरि, आल्हादेव

5. हैला ख्याल

(जोर-जोर से बोल के)

- मुख्य क्षेत्र : लालसौट (दौसा)
- सवाई माधोपुर – प्रारंभ होने से पूर्व
- मुख्य वाद्य यंत्र – ''नौबत''
- बम वाद्य यंत्र का प्रयोग

6. ढप्पाली ख्याल

- मुख्य वाद्य यंत्र : डफ (चंग)
- मुख्य क्षेत्र : भरतपुर, अलवर के लक्ष्मणगढ में

7. कन्हैया ख्याल

- प्रमुख क्षेत्र : करौली
- इसमें सूत्रधार – ''भेडिया'' कहते है ।
- वाद्य यंत्र – नौबत, घेरा, मंजीरा व ढोलक

भेंट के दंगल:

मुख्य क्षेत्र – बाडी, बसेडी (धौलपुर)

8. तुर्रा कलंगी

प्रवर्तक : तुकनगीर, शाहअली

- चंदेरी के राजा (मेदिनीराय) ने इनके अभिनय से खुश होकर इन्हे तुर्रा, कलंगी भेंट दिये थें ।
- सहेदू सिंह, हमीद बेग ने इसे चित्तौड में लोकप्रिय किया ।
- इसमें 2 पक्ष आपस संवाद करते है जिसे ''गम्मत'' कहा जाता है ।

2 पक्ष
1. शिव पक्ष
2. पार्वती पक्ष

- शिव पक्ष के झण्डे का रंग भगवा तथा पार्वती पक्ष के झण्डे का रंग ''हरा'' होता है ।
- एकमात्र लोकनाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है ।
- एकमात्र लोकनाट्य जिसमें दर्शक भी भाग लेते है ।

मुख्य कलाकार

- चेतराम
- ओंकार सिंह
- जयदयाल सोनी

मुख्य केन्द्र

- घोसुण्डा
- निम्बाहेडा

→ चित्तौडगढ

नौटंकी

- भरतपुर में लोकप्रिय है ।
- प्रचलन – डींग निवासी भूरीलाल ने किया ।
- ''हाथरस शैली'' से प्रभावित है ।
- इनमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है । महिला तथा पुरूष दोनों भाग लेते है ।
- प्रवर्तक :भूरीलाल जी,
- मुख्य कलाकार : गिरिराज प्रसाद
- मुख्य कहानियाँ :
  1. अमर सिंह राठौड
  2. आल्हा – ऊदल
  3. सत्यवान – सावित्री
  4. लैला–मंजनू

रम्मत

- जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है ।
- होली के समय ''फाल्गुन शुक्ल अष्टमी'' से लेकर चतुर्दशी तक रम्मत लोकनाट्य किया जाता है ।
- मुख्य वाद्य यंत्र नगाडा तथा ढोलक है ।
- रम्मत मे रंगमंचीय सजावट नहीं होती है ।
- रम्मत शुरू करने से पहले ''रामदेवजी का भजन'' गाते है ।
- रम्मत का अर्थ–रमने वाला अर्थात् खेल होता है ।
- जैसलमेर में इसे ''तेज कवि'' ने लोकप्रिय किया । इसने ''स्वतंत्र बावनी'' की रचना की तथा इसे गांधीजी को भेंट किया । रम्मत के मुख्य कलाकार तेरिये होते है ।
- तेज कवि ने अपने नाटकों में अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया
- बीकानेर में ''पुष्करणा ब्राह्मणों'' द्वारा रम्मत का आयोजन पाटो पर किया जाता है ।
- आचार्यो का चौक – अमरसिंह राठौड की रम्मत
- बारह गुवाड – हेडाउ – मेरी की रम्मत (इसे जवाहर लाल जी ने प्रारम्भ किया था)
- बीकानेर में रम्मत के मुख्य कलाकार:
  1. फागु महाराज
  2. तुआ महाराज
  3. मनीराम व्यास
  4. तुलसी दास

तमाशा

- मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है ।
- ''सवाई प्रताप सिंह'' के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ ।
- इसके लिए ''बंशीधर भट्ट'' को महाराष्ट्र से लेकर आयें ।
- जिस खुले मैदान में तमाशा का आयोजन होता है उसे ''अखाडा'' कहा जाता है ।
- जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना ''गौहर जान'' तमाशा में भाग लेती थी ।
- वाद्य यंत्र – हारमोनियम, तबला, सारंगी, नक्कारा

मुख्य कहानियाँ

1. जुठ्ठन मियां का तमाशा (शीतला अष्टमी)
2. जोगी – जोगण का तमाशा

   मुख्य कलाकार : गोपी कृष्ण जी भट्ट – तमाशा के उस्ताद

   संगीत प्रभाकर की उपाधि

गवरी

- राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य इसे ''भेरू लोकनाट्य'' भी कहते है ।
- यह मेवाड के भीलों का धार्मिक लोकनाट्य है जो रक्षाबन्धन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है ।
- इसमें केवल पुरूष भाग लेते है ।
- सम्पूर्ण भारत मे दिन में प्रदर्शित होने वाला भीलों का एकमात्र लोकनाट्य ।

मुख्य वाद्य यंत्र

1. माँदल
2. थाली

- यह लोकनाट्य ''शिव–भस्मासुर'' की कहानी पर आधारित है । इसमें शिव को ''राई बुडिया'' तथा पार्वती को 'गवरी' कहा जाता है ।
- इसका सूत्रधार ''कुटकुडिया'' कहलाता है ।
- हास्य कलाकार ''झटपटिया'' कहलाता है ।

मुख्य कहानियाँ

1. कान–गुजरी
2. बन्जारा – बन्जारी
3. अकबर – बीरबल

अलग अलग कहानियों को जोडने के लिए बीच में नृत्य किया जाता है, जिसे ''गवरी की घाई'' कहते है ।

स्वांग

- ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्रों के कपडे पहनकर उनका अभिनय करना स्वांग कहलाता है ।
- इसके कलाकार को ''बहुरूपिया'' कहा जाता है ।
- भीलवाडा में लोकप्रिय है ।
- होली के अवसर पर किया जाता है ।

राजस्थान की हस्तकला

मीनाकारी – 3 प्रकार की है ।

थेवा कला

- ''कांच में सोने की कारीगरी'' से आभूषण बनाये जाते है ।
- मुख्य केन्द्र : प्रतापगढ
- प्रवर्तक : नाथू जी सोनी
- (''महेश राज सोनी'' को पद्मश्री मिल चुका है ।)
- जस्टिन बकी (अंग्रेज अधिकारी) ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया ।
- इसको गोपनीय रखा जाता है इसी कारण यह विकसित नहीं हो पाई ।
- तारकशी (चाँदी की मीनाकारी) – नाथद्वारा (राजसमन्द)
- चाँदी का काम तारकशी कहलाता है ।
- रेतवाती कला – कोटा और जयपुर की प्रसिद्ध है ।
- मुरादाबादी (पीतल की मीनाकारी) – अलवर तथा जयपुर
- कलाकर – जान नूर मोहम्मद और अब्दुल रउजाक कुरैशी
- ताँबे पर मीनाकारी भीलवाडा की प्रसिद्ध है ।

टेराकोटा

- मिट्टी को पकाकर उसके मूर्तियाँ और खिलौने बनाये जाते है ।
- खडित मूर्तियों को सम्मानपूर्वक पानी में पदराया (प्रवाहित) किया जाता है ।
- सुनहरी टेराकोटा – बीकानेर की प्रसिद्ध
- सफेद व गुलाबी टेराकोटा – डैसलमेर की प्रसिद्ध

मुख्य केन्द्र:

1. मोलेला (राजसमन्द)
   यहाँ के मोहनलाल कुमावत को पदम्श्री मिला है ।
2. हरजी (जालौर)
   यहाँ पर देवताओं के घोडे बनाये जाते है ।
3. बडोपल (हनुमानगढ)

- यहाँ से प्राचीनकाल की टेराकोटा प्राप्त हुई है ।

नोट : यहाँ पर ''पक्षी अभयारण्य'' स्थापित किया जा रहा है ।

ब्लू पॉटरी

- कालचीनी भी कहा जाता है ।
- चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनो पर नीले रंग के चित्र बनाये जाते है ।
- मुख्य केन्द्र : जयपुर
- कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है ।
- इन्होंने नीले रंग के अलावा भी अन्य रंगों का प्रयोग किया ।
- खुर्जा गांव (उत्तरप्रदेश) की सुप्रसिद्ध ब्लू पॉटरी मशीन से बनती है ।

ब्लैक पॉटरी

- कोटा

मीनाकारी

- सोने के आभूषणों में रंग चढाया जाता है ।
- मुख्य केन्द्र: जयपुर
- मानसिंह आमेर के राजा ने लाहौर से इसके कलाकारों को बुलाया था ।
- कुदरत सिंह को इसके लिए पदम्श्री मिल चुका है ।
- कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है ।

रंगाई – छपाई

(A) अजरख प्रिन्ट:
मुख्य केन्द्र : बाडमेर
- नीले रंग का प्रयोग अधिक
- ज्यामितीय अलंकरण अधिक
- तुर्की शैली का अधिक प्रभाव

(B) मलीर प्रिन्ट
मुख्य केन्द्र : बाडमेर
- काले व कत्थई रंग का प्रयोग अधिक

(C) सांगानेरी प्रिन्ट
काले व लाल रंग का प्रयोग अधिक
- मुन्ना लाल गोयल ने इसे प्रसिद्ध किया ।

(D) बगरू प्रिन्ट : रामकिशोर छीपा को 2009 में पद्मश्री
- प्राकृतिक रंगो का प्रयोग किया जाता है ।
- वेलबूटे (फूल-पत्तियाँ) की छपाई की जाति है ।

(E) आजम प्रिन्ट
आकोला (चित्तौडगढ)

(F) जाजम प्रिन्ट
चित्तौडगढ
गाडिया लोहार की महिलाओं के कपडे इसी प्रिन्ट में बनाये जाते हैं ।

(G) लहरिया :
मुख्य केन्द्र : जयपुर, पाली

(H) चुनडी : जोधपुर

कपडे की कला (2 प्रकार)

↓

1. रंगाई 2. छपाई

जाति – नीलगर/रंगरेज जाति – छीपा

उपनाम – डीनगीरी कला ठप्पा, भांत व बतकाडे छपाई मे काम आने वाले औजार हैं।

बगरू प्रिन्ट – 2009 ई. में रामकिशोर को पद्म श्री अवार्ड मिला।

दाबू प्रिन्ट – अकोला (चित्तौडगढ)

- इस प्रिंट मे जिस स्थान पर रंग नहीं चढता है उसे स्थान को लेई या लुगदी से दबा देते हैं।
- मोम का दाबू – सवाई माधोपुर
- मिट्टी का दाबू – बालोतरा (बाडमेर)
- गेहूँ व बींधण का दाबू – सांगानेर (जयपुर)

बंधेज कला

- बंधेज मण्डी – जोधपुर
  प्रसिद्ध कलाकर – तैयब जी
- बारीक बंधेज हाडौती का प्रसिद्ध है ।
- कत्थई रंग, मोर और इमली का चित्रण सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है ।

पोमचा – दो रंग का होता है ।

- पीला पोमचा पुत्र प्राप्ति पर ओढा जाता है।
  पीला पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है।
- गुलाबी पोमचा – पुत्र प्राप्ति पर प्रसुप्ति महिला द्वारा ओढा जाता है।
- चीड का पोमचा – हाडौती का प्रसिद्ध है जो काले रंग का होता है जो विधवा महिला द्वारा ओढा जाता है।

नोट – दुल्हन की ओढनी को 'पंवरी' कहते हैं।

- पिछवाईयाँ – नाथद्वारा की प्रसिद्ध
  कलाकर – नरोत्तम लाल षर्मा

बन्धेज प्रिन्ट : मुख्य केन्द्र : जयपुर
- इसे ''टाई एण्ड डाई'' कहा जाता है ।

बादले

- डिंक (जस्ते) के बने बर्तन जिन पर कपडे या चमडे की परत चढायी जाती है । इनमें पानी ठण्डा रहता है ।
- मुख्य केन्द्रः जोधपुर

जस्ते की मूर्तियाँ : जोधपुर

काष्ठ कला : बस्सी (चित्तौडगढ)

रमकडा उद्योग

- गलियाकोट (डूँगरपुर) (रमकडे–खिलौने)

खेसले : लेटा (जालौर)

पाव रजाई : जयपुर

दरियाँ

- टांकला (नागौर)
- लवाण (दौसा)
- सालावास (जोधपुर)

गलीचे/नमदे

- जयपुर, टोंक
- बीकानेर व जयपुर की जेल में कैदियों द्वारा गलीचे बनाये जाते हैं ।
- ऊन के कंबल – जयपुर

मिरर वर्क : जैसलमेर

पेच वर्क : शेखावाटी

गोटा किनारी

खण्डेला (सीकर) प्रकार
1. किरण
2. बाँकडी
3. लप्पा – लप्पी

तारकशी के गहने

- चाँदी के पतले तारों से आभूषण बनाये जाते हैं ।
- मुख्य केन्द्र : नाथद्वारा (राजसमन्द)

कोटा डोरिया : (मंसूरिया कला)

- मुख्य केन्द्रः
- कैथून (कोटा) मांगरोल (बांरा)
- जालिम सिंह झाला इसके कलाकार मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेकर आया था ।
- इसे मंसूरिया कला भी कहते हैं ।
- नोटः कैथून में विभीषण का मन्दिर है ।

राजस्थान में खनिज

- राजस्थान खनिज संसाधनों की दृष्टि से सम्पन राज्य है । इसे खनिजों का संग्रहालय एवं अजायब घर कहा जाता है ।
- देश की 19 प्रतिशत कार्यरत खानें राजस्थान में है । जिनका देश में उत्पादन की दृष्टि से 9 वां स्थान है ।
- डोस्पार, सैलेनाईट, गार्नेट, वॉलस्टोनाइट, पन्ना के उत्पादन में राजस्थान देश में एक मात्र राज्य है ।

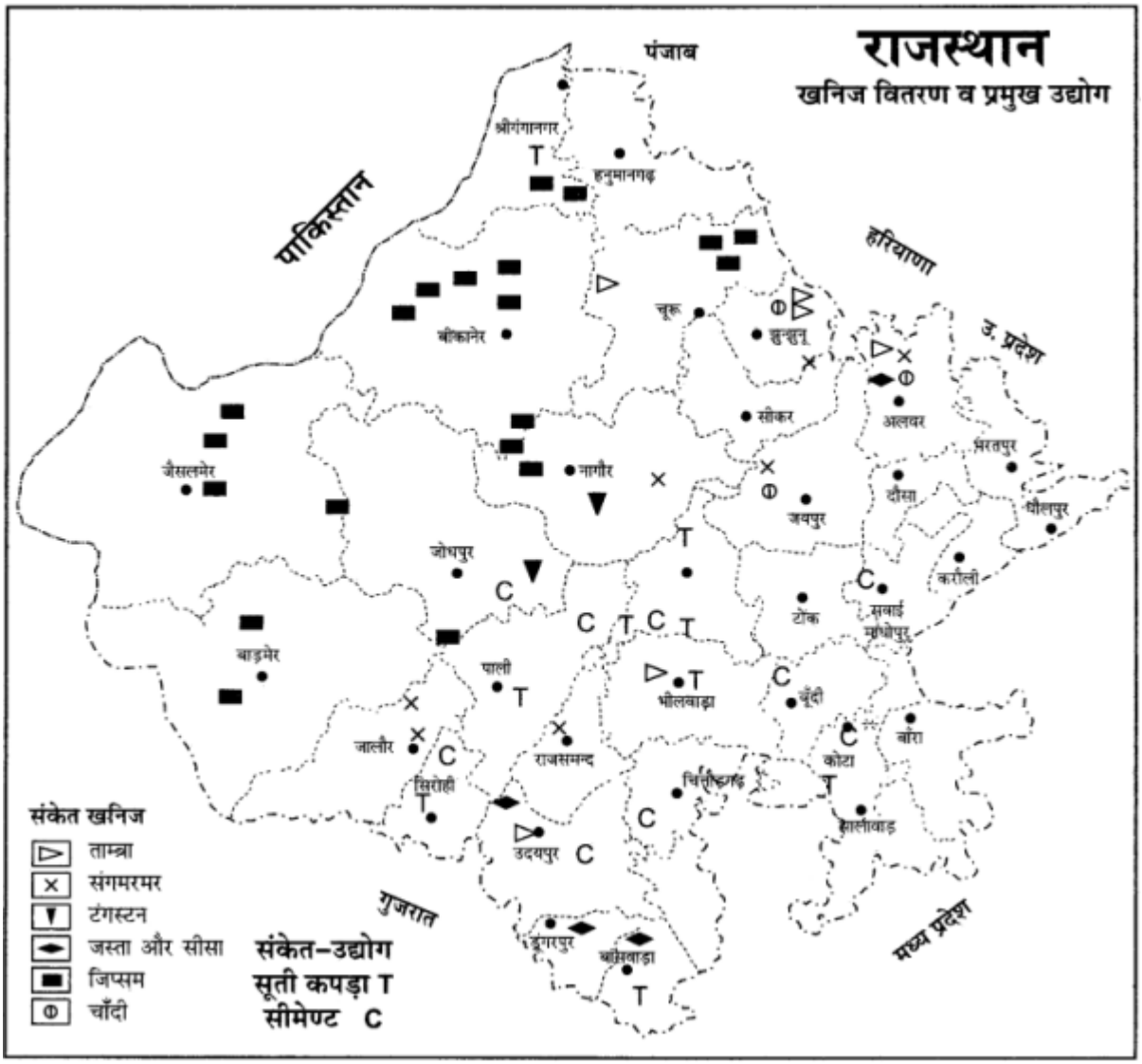

मानचित्र – खनिज वितरण व प्रमुख उद्योग

खनिज दृष्टिकोण

भण्डारण	उत्पादन	विविधता	आय
राजस्थान द्वितीय स्थान	द्वितीय उत्पादित खनिज–57	प्रथम खनिज प्रकार – 81	आठवां

1. खनिज भण्डारण

खनिज भण्डारण सर्वाधिक अरावली में पाया जाता है, इस कारण अरावली को खनिजों का भण्डारगृह कहा जाता है ।

2. खनिज उत्पादन

राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन का 9 प्रतिशत उत्पादित करता है

जिसमें धात्विक – 15 प्रतिशत अधात्विक–25 प्रतिशत अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है ।

3. खनिज विविधता

खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है

4. खनिज आय

खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान पिछडा हुआ राज्य है क्योकि यहाँ से मुख्यतः अधात्विक खनिज का उत्पादन होता है ।

राज्य की खनिजों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है ।

खनिज वर्गीकरण		
धात्विक	अधात्विक	ईधन खनिज
वे खनिज जिनसे धातुओं की रासायनिक तथा क्रियाओं द्वारा परिष्कृत या कार्बन अलग किया जा सकता है प्रयोग – वे सामान्यतः अयस्क के होता है । रूप में पाये जाते है । लौह धात्विक : कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैगनीज, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम	वे खनिज जिन्हें रासायनिक क्रिया से परिष्कृत कर मूल खनिज से पृथक नही किया जा सकता है, इन्हे औद्योगिक खनिज भी कहा जाता है • अभ्रक • जिप्सम • पत्थर • क्ले	वे खनिज जो प्रत्यक्ष ऊर्जा प्रदान करते है जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है । इनका ईधन के रूप में ऊर्जा खनिज : • कोयला • पेट्रोलियम • प्राकृतिक गैस
अलौह धात्विक : सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता, टिन, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मर्करी		

धात्विक खनिज

लौह अयस्क

हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है ।

राजस्थान का प्रथम लौह अयस्क परिष्करण संयंत्र–पूर भीलवाडा तिरंगा पहाडी पर स्थापित किया गया था ।

- हमारा लौहे का बडा ग्राहक जापान (68 प्रतिशत) है ।

प्रमुख स्थल

- जयपुर – चौमू, टोडा–चिपलाटा थोई बनिया का वास, तातेरी बांगावास, भट्टो की गली, मोरीजा – बानोला ।
- सीकर – नीमकाथाना – बगोली, सराय – पंचलंगी
- झुंझुनूँ – खेरडी, डाबला–सिघाना
- उदयपुर – नाथराकीपाल, हुंडेर
- भीलवाडा, डुंगरपुर, बांसवाडा तक पेटी काकरोली, उदयपुर
- दौसा – नीमला गांव
- बूंदी – लोहारपुर
- डुंगरपुर – लोहरिया, खाचरिया, तालवारा भीलवाडा – पादरपाल, डाग, इन्दगढ,
- बांसवाडा – कमलपुर, लामया

मैंगनीज

अवसादी शैलों से प्राप्त होने वाला यह खनिज राज्य में कम मात्रा में पाया जाता है ।

रंग – काला

उपयोग – लोह इस्पात (लोहे को कठोर करने के लिए 1 टन में 6 kg.)

बांसवाडा – लीलवानी, नराडिया, सिवोनिया, कालखुन्टा, कासला, सागवा, इटाला, तिम्यामौरी, खेडिया, काचला, तलवाडा आदि ।

उदयपुर– नेगडिया स्वरूपपुरा, रामौरान, जयपुर व सवाईमाधोपुर मे क्वार्टजाइट शिलाओं की दरारों में मैंगनीज पाया जाता है ।

लोकनीति

- लोकनीति का निर्माण लोक प्रशासन का सार है। नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन व्यवस्था की मुख्य क्रियाओं में से एक है। नीति का मतलब यह निर्णय करना है–क्या किया जाए, कब किया जाये, कहाँ किया जाए और कैसे किया जाए।
- पीटर ओडेगार्ड के अनुसार–"नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुडवाँ बच्चे हैं जो एक–दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते हैं।"
- प्रो. एल.डी. व्हाईट के अनुसार–"सार्वजनिक नीति का प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है।"
- एपलबी के अनुसार –"लोक प्रशासन नीति निर्माण है।"
- ड्वाइट वाल्डो के अनुसार –"लोक सेवकों द्वारा लोकनीति का, लोक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया प्रबन्धन और व्यवस्थापन ही लोक प्रशासन है।"
- नीति–वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की प्रस्तावित रूपरेखा व क्रियाविधि है।
- इस प्रकार नीतियाँ उद्देश्यों को निश्चित अर्थ एवं मूर्त रूप प्रदान करती है।
- डिमॉक के अनुसार –"नीतियाँ सजगता से निर्धारित आचरण के वे नियम है, जो प्रशासनिक निर्णयों को मार्ग दिखाते है ।"
- पॉल जे फ्रेडरिक के अनुसार –"इस परिस्थति में क्या करना है, क्या नही करना है के संबंध में किए गये निर्णय ही नीतियाँ है।"

लोकनीति के लक्षण

1. लोकनीति सकारात्मक व नकारात्मक होती है।
2. लोकनीति जनहित पर आधारित है।
3. लोकनीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम है।
4. लोकनीति दिशा–निर्देश रेखांकित करती है।
5. लोकनीति गतिशील प्रक्रिया है।
6. लोकनीति सरकार के उद्देश्यों तक पहुँचने का साधन है।
7. लोकनीति एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करती है।
8. लोकनीति परिणामोन्मुख होती है और इसमें अधिक आधुनिक तकनीक के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
9. लोकनीति संविधान, कानून, अध्यादेश विनियम, कार्यकारी आदेश अथवा न्यायिक निर्णय के रूप में हो सकती है।

भारत में नीति–निर्माण के अंग

1. संविधान
2. विधानमण्डल
3. मंत्रिमण्डल
4. नीति आयोग
5. लोक सेवाएँ
6. न्यायपालिका
7. मीडिया

8. दबाव समूह
9. राजनीतिक दल
10. व्यवसायिक सभाएँ

लोकनीति निर्माण की विधि

1. समस्या की पहचान
2. विशेषज्ञ संस्था का गठन
3. व्यापक रूपरेखा निर्माण
4. ड्राफ्ट नीति का प्रकाशन
5. अन्तिम रूप से तैयार नीति घोषित

लोकनीति क्रियान्वयन में बाधाएँ

1. पारम्परिक प्रशासन तंत्र का होना।
2. जनसहयोग की कमी।
3. उद्देश्यों की अस्पष्टता।
4. समन्वय की कमी।
5. राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार।
6. अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप।

लोकनीति के प्रकार

नियंत्रक नीतियाँ – वे नीतियाँ जो सरकार के नियंत्रण संबंधी कार्यों को उजागर करती है। जैसे–उद्योग, व्यापार आदि।

वितरण संबंधी नीतियाँ – इस नीति का उद्देश्य पिछडे वर्गों को मुख्य धारा से जोडना है।

मूलभूत नीतियाँ – सम्पूर्ण समाज के सामान्य व सर्वांगीण विकास व कल्याण से संबंधित होती है। जैसे–शिक्षा, चिकित्सा आदि।

संघटक नीतियाँ – ऐसी लोक नीतियाँ जो ज्ञान या तकनीकी विशेषज्ञ उपकरणों पर आधारित होती है। ये नीतियाँ देश की सुरक्षा, राज्य के हित तथा व्यापक संदर्भों से युक्त होती है, संघटक नीतियाँ कहलाती है।

क्षेत्रक नीतियाँ – लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के अनुसार विषयवार या विशेषज्ञता के अनुसार जो नीतियाँ बनाती है, वे क्षेत्रक नीतियाँ कहलाती है।

- नियामकीय नीतियाँ – व्यापार, खनिज नीतियाँ
- आर्थिक नीतियाँ – औद्योगिक नीति
- सामाजिक नीति – महिला नीति, जनसंख्या नीति

नीति विश्लेषण के प्रमुख प्रतिमान

1. सांस्थानिक प्रतिमान – नीति निर्माण में संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी बात को दूसरे षब्दों में कहे तो नीति जब तक लोक नीति नहीं कहलाती है जब तक की उसके निर्माण तथा क्रियान्वयन में सरकारी संस्थाएँ साथ नही होती है।
2. नव सांस्थानिक प्रतिमान – ये मुख्यतः राजनीतिक संस्थाओ से संबंधित है।

3. क्रीडा प्रतिमान – यह मुख्यतः विदेश नीति, रक्षा नीति, अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधो, युद्ध एवं षांति, परमाणु अस्त्रों तथा विधायिका में गठबंधनों इत्यादि के समय क्रीडा प्रतिमान प्रयुक्त होता है, किन्तु लोकनीति में इस प्रतिमान का उपयोग सीमित ही माना जाता है।
4. तार्किक चयन प्रतिमान – विन्सेण्ट, ऑस्ट्रोम, तुलोक निस्कनैन तथा कैनेथ जे.ऐरो भी इस प्रतिमान के प्रबल समर्थक है।

विधिक अधिकार

- वे अधिकार जो विधि द्वारा संरक्षित है एवं संविधान व व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियम द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते है।
- इहरिंग के अनुसार – "अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है।"
- सालमण्ड के अनुसार – "विधिक अधिकार विधि के नियम या शासन द्वारा मान्य और सुरक्षित हित है।"
- हॉलैण्ड के अनुसार – "विधिक अधिकार का अर्थ बल से अलग है अर्थात् विधिक अधिकार में राज्य या विधि का बल होता है।"
- नागरिकों को प्रदान किये गये विधिक अधिकार निम्न है–

1. संविधान द्वारा प्रदत्त
   - मतदान का अधिकार – अनुच्छेद 326
   - सम्पत्ति का अधिकार – अनुच्छेद 300(अ)
   - निःशुल्क विधिक सहायता – अनुच्छेद 39(अ)

2. संसद द्वारा प्रदत्त

   नागरिक अधिकार पत्र
   - सिटीजन चार्टर एक प्रकार का दस्तावेज है, जो किसी संगठन की सेवाओं की मानकता, सूचना, विकल्प एवं परामर्श तथा पहुँच व शिकायत निवारण तंत्र संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाता है।
   - सर्वप्रथम सिटीजन चार्टर व्यवस्था जॉन मेजर के प्रयासो से ब्रिटेन में वर्ष 1991 में लागू हुई। जॉन मेजर द्वारा सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिको को सम्मानित और पुरस्कृत करने की एक योजना "चार्टर मार्क स्कीम" के नाम से प्रारम्भ की गई।
- भारत में वर्ष 1996 में मुख्य सचिवो के सम्मेलन "An Agenda for Effective and Responsive Administration" तथा वर्ष 1997 में मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन से सिटीजन चार्टर व्यवस्था की शुरूआत हुई।
- केन्द्र सरकार ने सर्वप्रथम सिटीजन चार्टर, 1997 में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया था।
- राजस्थान में वर्ष 1998 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अर्थात् नागरिक आपूर्ति विभाग तथा वर्ष 1999 में राजस्व मण्डल ने लागू किया।
- एनजीओ कॉमन कॉज (संचालक एस.डी. षौरी) द्वारा संचालित आन्दोलन ने भारत में इसकी भूमिका बनाई।

सिटीजन चार्टर में शामिल बिन्दु
- दृष्टिकोण व मिशन वक्तव्य।
- संगठन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा।

राजस्थान आर्थिक–समीक्षा 2021–22

जारीकर्ता – आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान (जयपुर), मुख्यालय–जयपुर

कब जारी – सामान्यतः आर्थिक समीक्षा बजट से पूर्व जारी किया जाता है।

क्यों जारी – राज्य की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने हेतु

वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य

1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (SGDP)
2. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (SNDP)
3. सकल राज्य मूल्यवर्धन
4. शुद्ध राज्य शुद्ध वर्धन/शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
5. प्रति व्यक्ति आय
6. सकल पूँजी निर्माण
7. संख्यिकीय सूचक
   - थोक मूल्य सूचकांक
   - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

- राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को ''सकल घरेलू'' कहा जाता है।
- GSDP अनुमानों को प्रचलित कीमत तथा स्थिर कीमतों पर अनुमानित किया जाता है ।
- वर्तमान में GSDP की स्थिर कीमत वर्ष–2011–12 ली जाती है ।
- GSDP राज्य के आर्थिक विकास का सूचक कहा जाता है । (स्थिर मूल्य का)

GSDP

2021-22

स्थिर मूल्यों पर

2021-22 – 7.33 लाख करोड़ (+11.4% वृद्धि)

↑

2020-21 – 6.60 लाख करोड़

चालू कीमतों पर

2021-22 – 11.96 लाख करोड़ (+18.4% वृद्धि)

↑

2020-21 – 10.13 लाख करोड़

2. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

- सकल घरेलू उत्पाद, समंको में से ''सकल स्थाई पूँजीगत उपयोग को घटाकर'' शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है ।

NSDP = GSDP – सकल स्थायी पूँजीगत उपयोग

NSDP

2021-22

स्थिर कीमतों पर

2021-22 – 6.48 लाख करोड़ (+11.05% वृद्धि)

↑

2020-21 – 5.84 लाख करोड़

प्रचलित कीमतों पर

2021-22 – 10.79 लाख करोड़ (+18.01% वृद्धि)

↑

2020-21 – 9.14 लाख करोड़

3. **ग्रामीण श्रमिकों हेतू CPI**
   - आधार वर्ष–2012
   - श्रम ब्यूरों, शिमला द्वारा जारी
4. **सामान्य CPI**
   - आधार वर्ष–2012

- NSO = राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी

CSO NSSO

NSO = वर्तमान में

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

1. राजस्थान की GSVA (कृषि)

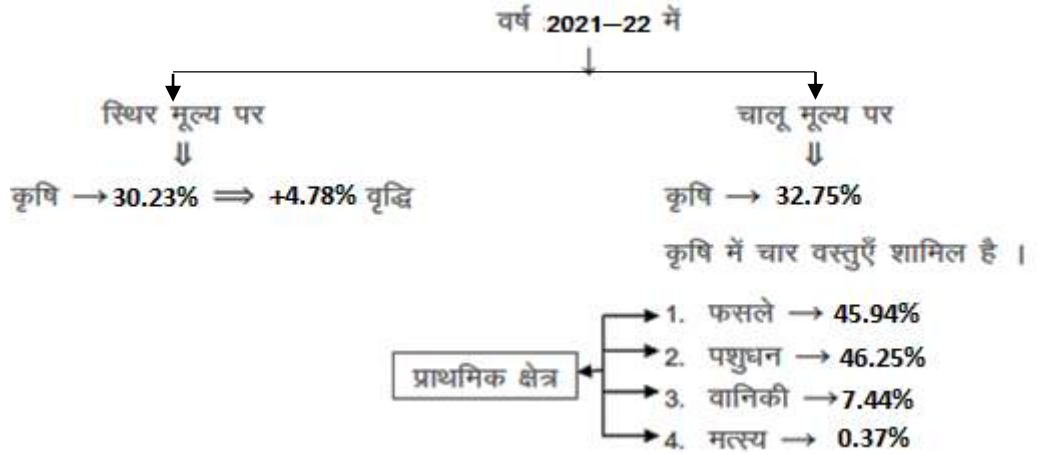

2. भू–उपयोग

2019–20 के आँकड़े

↓

342.90 लाख हेक्टेयर

↓

1. 52.58% (180.32 लाख हेक्टेयर) ⟹ शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
2. 10.84% (37.17 लाख हेक्टेयर) ⟹ बंजर भूमि
3. 8.08% (27.70 लाख हेक्टेयर) ⟹ वानिकी क्षेत्र
4. 6.92% (23.72 लाख हेक्टेयर) ⟹ ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि
5. 6.25% (21.42 लाख हेक्टेयर) ⟹ अन्य चालू पड़त भूमि
6. 5.85% (20.07 लाख हेक्टेयर) ⟹ कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि
7. 4.54% (15.55 लाख हेक्टेयर) ⟹ चालू पड़त भूमि
8. 4.86% (16.67 लाख हेक्टेयर) ⟹ स्थायी चारागाह

3. मानसून

- राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है ।
- राजस्थान में मानसून के पँहुचने की सामान्य तिथि 15 जून हैं ।

कृषि उत्पादन

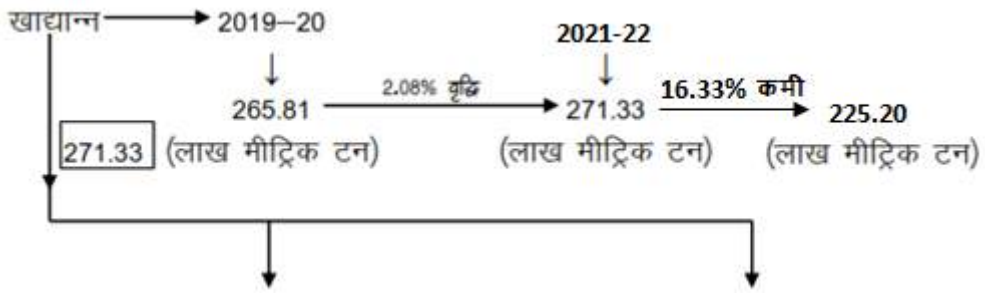

- इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
- केन्द्र–60 तथा राज्य–40
- 2007–08 में → गेंहूँ (14 जिले), दलहन, चावल
- 2012–13 में → मक्का (5 जिले), जौ (7 जिले)
- 2018–19 में → ज्वार (न्यूट्रीसियल)
- बाजरा (पौस्टिक अनाज)

नोट –

- इसमें व्यापारिक फसल कपास को भी शामिल कर लिया गया ।
- तिलहन को इसमें शामिल नहीं किया गया ।

5. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन

- केन्द्र सरकारद द्वारा, केन्द्र 60% तथा राज्य 40% योगदान
- (1 अप्रैल, 2014) से

उद्देश्य

1. कृषि विस्तार का सशक्तिकरण
2. कृषि में उचित तकनीकों को प्रोत्साहन
3. कृषि विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए
4. कृषि पंजीयन को बढ़ावा

इस मिशन के अर्न्गत चार उप मिशन है ।

1. कृषि विस्तार पर उप मिशन
2. कृषियंत्रीकरण पर उप मिशन
3. बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन
4. कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान

- केन्द्र–60 तथा राज्य–40

6. राष्ट्रीय खेती मिशन

शुरू – वर्ष 2014–15 से
वित्त पोषण – केन्द्र–60 तथा राज्य–4

टिकाऊ खेती

- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा जल प्रबंधन के माध्यम से
  कृषि उत्पादकता के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जा सके।
- इस मिशन में चार उप मिशन चलाए जा रहे है ।
  1. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
  2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
  3. परंपरागत कृषि विकास योजना
  4. कृषि वानिकी पर उपमिशन

7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

शुरूआत – 19 फरवरी, 2015

उद्देश्य

मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की सही जानकारी प्राप्त करना । (12 तत्व की जाँच)

योजना

- मृदा की जाँच के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा (3 वर्ष की अवधि के लिए)
- 14 करोड़ कार्ड उपलब्ध कराए जायेंगे ।

स्लोगन

- ठसका स्लोगन "स्वास्थ्य धरा, खेत हरा" है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य–गुजरात

8. परंपरागत कृषि विकास योजना

- वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा लान्च की गई।

उद्देश्य

- जैविक कृषि को बढ़ावा देना जिससे रासायनिक खाद्य कीटनाशक से होने वाली बीमारियों से किसानों की सेहत की सुरक्षा हो सके ।
- मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट होने से बचाया जा सके ।

योजना

- इस योजना के अंतर्गत 50 से ज्यादा किसान जैविक खेती करने के लिए 50 एकड़ जमीन वाले समूह का निर्माण करेंगे ।
- हर एक किसान को 3 वर्ष में बीज के लिए फसलों की कटाई और बाजार में उपज परिवहन के लिए ₹ 20,000/– प्रति एकड़ उपलब्ध कराए जायेंगे
- अब इसे क्लस्टर आधार (लगभग प्रति 1000 हेक्टेयर पर) शुरू किया गया है ।

औद्योगिक विकास

1. उद्योग, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रों में शामिल किये जाते है ।
2. GSVA में उद्योगों का योगदान
   ↓
   2021–22 में ⟶ चालू कीमत पर = 24.67%
   विनिर्माण ⟶ 2021–22 में ⟶ 10.06%
   खनन क्षेत्र ⟶ 2021–22 में ⟶ 2.78%
3. राज्य से निर्यात बढ़ाने हेतु ''निर्यात संवर्द्धन परिषद और निर्यात संर्वद्धन औद्योगिक पार्क'' का विकास किया गया है ।
4. औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (IIP)

- CSO ⟶ NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) द्वारा जारी होता है।
- आधार वर्ष 2011–12 है।
- मासिक आधार पर तैयार होता है।
- राज्य में औद्योगिक निष्पादन का संकेत देने हेतु यह सूचकांक जारी किया जाता है ।
- यह सूचकांक 3 समूहों पर आधारित है ।
  1. विनिर्माण क्षेत्र
  2. खनन क्षेत्र
  3. विद्युत क्षेत्र
- इस सूचकांक में 2016–17 से 2018–19 तक निरंतर प्रगति एवं वर्ष 2019–20 व 2020–21 में कमी प्रदर्शित की गयी है ।

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की उद्योग आधार ज्ञापन अधि–सूचना अधिनियम 2015 राजस्थान राज्य में लागू की गई ।
- इसका ऑनलाइन पंजीयन 18 सितम्बर, 2015 से प्रारम्भ किया गया है ।
- भारत सरकार के U.A.M. (उद्योग आधार मैमोरेंडम) पोर्टल पर कोई भी MSME मैमोरेंडम दाखित कर सकता है ।
- भारत सरकार द्वारा के स्थान पर 1 जुलाई, 2020 से "उद्यम रजिस्ट्रीकरण" प्रारम्भ किया गया है।

6. राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेस्लिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019

अधिसूचित – 17 जुलाई, 2019

- इस अधिनियम में ''राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल'' पर नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमो की स्थापना का प्रावधान है ।
- इसमें छूट–3 वर्ष है।

7. राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

घोषणा – औद्योगिक नीति 1994 में की गई

प्रावधान

- इसमें 16 श्रेणियों में 33 उत्कृष्ठ निर्यातकों के चयन का प्रावधान है ।

अवॉर्ड

- ''लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवॉर्ड''
- राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् ⟶ 8 नवम्बर, 2019 गठन
- राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् ⟶ 25 अक्टूबर, 2019 को गठन किया

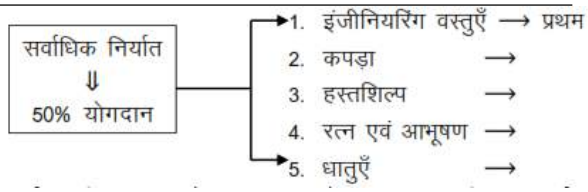

8. निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं प्रलेखन / दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

लागू – 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुई

क्रियान्वयन अवधि – 31 मार्च 2023 तक प्रशिक्षण

- 2 दिन का होता है।
- 2020–21 7 जिलों में प्रशिक्षण कार्य संचालित है।
  1. अजमेर
  2. झुँझुनूँ
  3. जालौर
  4. धौलपुर
  5. दौसा
  6. प्रतापगढ़
  7. टोंक

9. उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण

राज्य सरकार – भारत सरकार के ''उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की वार्षिक सुधार कार्य योजनाओं का अनुसरण एवं कार्यान्वयन'' कर रहा है ।

उद्योग विभाग

- 36 जिला उद्योग केन्द्र तथा 8 उपकेन्द्र है।
  MSME इनवेस्टर फैसिलिटी सेन्टर
- उद्योग विभाग द्वारा संचालित है।
- इसमें अजमेर, जयपुर, जोधपुर में सेन्टर है।
- उद्यमियों को सुविधाएँ प्रदान करने हेतु किया गया।
- राजस्थान (राज्य) के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो के विलम्बित भुगतान के निपटारे हेतु 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों के गठन के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है ।

10. औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (IEM)

- वृहद उद्योगो की स्थापना से संबंधित है।
- वर्ष 2020–21 से।
- 25 प्रस्ताव शामिल है।

11. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है।
- यह रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कार्य करती है

12. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना

- 17 दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ है।
- इसे राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया।